

व्यापार युद्ध : क्या यह अवैधीकरण की पूर्वपीठिका है ?*

बी. पी कानूनगो

आज यहाँ आकर मैं खुश हूँ और फॉरेक्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफएआई) एवं इस सम्मेलन के आयोजकों का आभारी हूँ कि मुझे इस समूह को संबोधित करने हेतु आपने आमंत्रित किया। खुशी इस बात की भी है कि मैं सिंगापुर में हूँ, एक ऐसा देश जो कि वैधीकरण की उपलब्धियों को वास्तव में साकार करता है और ऐसा देश जिसके साथ सांस्कृतिक, जातीय व आर्थिक क्षेत्रों में भारत के बहुविध संबंध थे और अभी भी हैं। विदेशी मुद्रा की माँग व आपूर्ति में मध्यस्थ विदेशी मुद्रा बाजार के पेशेवरों की संस्था एफएआई, शेष अर्थव्यवस्था के लिए 'कीमत देने वाले' का कार्य करती है और 1979 से फॉरेक्स बाजार में पारदर्शिता, पेशेवराना रवैया और नैतिक आचार को बढ़ावा देने में लगी हुई है। उनकी इस भूमिका की मैं प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी पूरी सक्षमता व निष्पक्षता से ऐसा करते रहेंगे।

विदेशी मुद्रा बाजार कई मायनों में अनूठा है। कोई भी विदेशी मुद्रा अपने क्षेत्र के बाहर मूलतः एक वस्तु है और इस प्रकार इसमें आस्ति (एसेट) के गुण होते हैं। लेकिन घरेलू मुद्रा में सामान्यीकृत विनिमय दर एक समष्टि आर्थिक चर है जिसका निर्धारण आर्थिक आधारों से होना अपेक्षित है और जो आर्थिक कारकों को प्रभावित करता है। सिद्धांतः अपने इस दोहरे आचरण के कारण, विनिमय दर में बड़ी अस्थिरता दिखती है व आर्थिक आधारों से सूचित मूल्य से विलग हो जाती है जिसके कारण नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यहाँ यह जरूर जोड़ दूँ कि बहुत ज्यादा अस्थिरता के बाद किसी विदेशी मुद्रा व्यापारी को सबसे अधिक विचलित करने वाली दूसरी कोई चीज है तो वह है बहुत कम अस्थिरता!

यह एक विसंगति है कि उलट-फेर करने वाले कई कारकों के बीच हाल के समय में वैश्विक मुद्रा बाजारों में अस्थिरता काफ़ी कम रही है। वस्तुतः जे पी मॉर्गन ग्लोबल एफएक्स वोलेटिलिटी

* श्री बीपी कानूनगो, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, फॉरेक्स एसोसिएशन आफ इंडिया कॉन्फ़रेंस में 10 अगस्त 2019 को दिया गया भाषण।

इंडेक्स 2014 के बाद से अब तक के अपने निम्नतम स्तर पर है। बाजार के सहभागियों ने इसे तूफान के पहले के सन्नाटे के रूप में देखा है और पहले की उन घटनाओं का जिक्र किया है जब इस तरह की ढलान के बाद अमेरिकी डॉलर तेजी से ऊपर गया। अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा घोषित 25-आधार-अंक की कटौती के बावजूद, यूएस डॉलर तेजी से ऊपर गया, शायद इस उम्मीद में कि भविष्य में और उदार (एकोमोडेटिव) कदम उठाए जाएंगे। इससे कम से कम अनिश्चितता तो रेखांकित होती ही है।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य बहुत उत्साहजनक नहीं है, यद्यपि अभी भी निराशावाद के लिए कोई जगह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) 2019 के वैश्विक वृद्धि अनुमानों को संशोधित करके घटाता जा रहा है पर 2020 का परिदृश्य अधिक सकारात्मक है। विकसित देशों में वृद्धि सुस्त बनी हुई है तथा हाल के वर्षों में वैश्विक वृद्धि में बड़ा योगदान देने वाली चीन व भारत समेत उभरती अर्थव्यवस्थाएं चुनौती का सामना करती प्रतीत हो रही हैं। एक ही समय में कई केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में की जा रही कटौती को देखते हुए उदार/निभावी (एकोमोडेटिव) मौद्रिक नीति का एक और दौर नहीं लगता।

दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक व्यापार तनाव आज चर्चा का प्रमुख विषय हैं। इस तनाव के जल्दी हल होने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं प्रतीत होती, न ही ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में यह बढ़ेगा या तेजी से हाथ से निकल जाएगा। व्यापार प्रशुल्कों (ट्रेड टैरिफ़) अवरोधों के जरिये स्पर्धात्मक संरक्षणवाद का जो भी राष्ट्रीय या आर्थिक तर्क हो, वैश्विक आर्थिक सुस्ती में इसका हाथ पक्का है। तथाकथित ब्रेकिजट, यूरोपीयन यूनियन से ब्रिटेन का निकलना भी अनिश्चितता से घिरा हुआ है और यह माना जा रहा है कि बे-सौदा (नो-डील) ब्रेकिजट उथल-पुथल का एक कारक अवश्य होगा। खाड़ी व अन्यत्र भी भू-राजनैतिक तनाव जोखिम पैदा कर रहे हैं जो मनोभावों पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं।

आईएमएफ की प्रधान अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था जिस नाजुक मोड़ पर है, उसका बड़ा कारण अपनी करनी है और अवैधीकरण के बारे में सोचना पूरी तरह अपरिपक्वता है। वैधीकरण के चक्र को उलटा नहीं जा सकता और यह सदियों से आगे बढ़ता आ रहा है। हाल के समय

में संचार व तकनीक में लंबी छलांगों के कारण इसमें प्रत्याशातीत प्रगति हुई है। अर्थव्यवस्थाओं, बाजारों, सामाजिक आदान-प्रदान, शिक्षा इत्यादि मानव अस्तित्व के सभी पक्ष आपस में गूँथे हुए हैं। सच है कि वैश्विकरण की प्रक्रिया अपने साथ समस्याएं व असंतोष लेकर आई है, लेकिन समझदारी इनका हल करने में है न कि प्रक्रिया को ही त्यागने में।

मुक्त व्यापार वैश्विकरण का एक प्रमुख आधार रहा है। आम तौर पर यह मानी हुई बात है कि राष्ट्रों के बीच खुले व्यापार से समृद्धि बढ़ती है। इसके पीछे तर्क वही है जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में है : विशेषज्ञता, तुलनात्मक लाभ और उत्पादकता के फायदे। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की तरह ही व्यापार के लाभ को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके अलावा मुक्त निर्यात और मुक्त आयात के प्रति दृष्टिकोण एक सा नहीं है। घरेलू रोजगार, वृद्धि व विदेशी मुद्रा में सहायक होने के कारण प्रत्येक देश जहाँ निर्यात (सिवाय तब जब व्यापार की शर्तें खराब हों), के पक्ष में होता है, वहीं आयात को लेकर नाक भौं सिकोड़ा जाता है क्योंकि देश को रोजगार, वृद्धि व विदेशी मुद्रा की हानि होती है। इससे प्रशुल्क (टैरिफ़) जैसे अवरोधी उपाय सामाने आते हैं और जब कोई पर्याप्त टैरिफ़ की बात करता है, तो सीधा-सादा अर्थ है संबंधित देश के लिए पर्याप्त न कि पूरे विश्व के लिए। और यदि व्यापार करने वाले सभी देश जवाबी टैरिफ़ लगाने लगे तो इसमें सबका नुकसान ही होगा जिससे वैश्विक व विभिन्न राष्ट्रों की समृद्धि पर अलग-अलग ढंग से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सामान्यतः यह माना जाता है कि चालू खाता घाटे को दूर करने में, विभिन्न शर्तों के तहत, विनिमय दर कुछ संतुलनकारी भूमिका निभाता है। व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) वाले देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ना चाहिए जिससे वहाँ के निर्यात महँगे व आयात सस्ते होंगे तथा व्यापार घाटा वाला देश हो तो इसका विपर्यय। इस प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बिना राष्ट्रीय प्राधिकारियों के दखल के, किस हद तक विनिमय दरें बाजार की ताकतों से तय होती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हाल के व्यापार तनाव के पहले मुद्रा मूल्य में हेर-फेर के आरोप धड़ल्ले से लग रहे थे।

व्यापार, विनिर्माण, सेवा, आपूर्ति श्रृंखला, पूँजी की आवा-जाही के बढ़ते वैश्विकरण ने जटिल अंतर्निभरताओं का एक जाल रच दिया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का बाह्य रूप भी काफ़ी बड़ा हो गया है। राष्ट्रीय सरकारों व नीति निर्माताओं को जहाँ अपने-अपने क्षेत्र के हित में कार्य करना होता है, शेष विश्व पर उनकी कार्रवाइयों का संपार्श्विक प्रभाव अहम हो सकता है। बड़े देशों के नेताओं की कार्रवाइयों में समन्वय अत्यंत आवश्यक हो गया है। याद रहे कि ऐसी समन्वित कार्रवाई से वैश्विक वित्तीय संकट को नियंत्रित करने में मदद मिली।

गवर्नर दास ने हाल में बोलते हुए अमेरिकी ट्रेज़री द्वारा 2015 से मुद्रा-मूल्य में हेर-फेर करने वाले देशों की निगरानी की ओर ध्यान खींचा जिसमें 2018 तक कुछ समय के लिए भारत का नाम था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आईएमएफ के चार्टर में इस बात के व्यापक प्रावधान हैं कि वह सदस्य देशों को व्यापार में अनुचित लाभ के लिए अपनी मुद्रा में हेर-फेर करने से रोक सकता है और किसी गलती को सुधारने की द्विपक्षीय कोशिश के बजाय बेहतर यही है कि मुद्रा हेर-फेर के आरोप संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए बहुपक्षीय ढाँचे का प्रयोग हो। वस्तुओं व सेवाओं में व्यापार व दूसरे क्षेत्रों में अनबन के मामलों में भी यही तर्क लागू होता है। पहले के प्रशुल्क व व्यापार संबंधी सामान्य करार (जीएटीटी) के पीछे यही उद्देश्य था जो कि अब डब्ल्यूटीओ है। वर्तमान व्यापार तनावों के हल का सर्वोत्तम रास्ता बहुपक्षीय है, अन्यथा जैसा कि पॉल क्रूगमैन ने कुछ समय पहले ट्वीट किया था, 'दीर्घकाल में विश्व पहले से दरिद्र होगा और अल्पकाल में भारी उथल-पुथल होगा।'

हाल के महीनों में भारतीय फॉरेक्स बाज़ार पर्याप्त स्थिर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रिज़र्व बैंक का कार्य विदेशी मुद्रा बाज़ार में व्यवस्था बनाए रखना है। इसका हस्तक्षेप केवल वेसी हठात् हलचलों को रोकने के लिए होता है जिनके पीछे कोई आर्थिक आधार नहीं होता। जैसा कि बार-बार कहा गया है, बाजार की कार्रवाइयां (ऑपरेशन्स) किसी लक्ष्य विनिमय दर या दरों का दायरा हासिल करने के लिए नहीं की जाती। यह अवश्य उल्लेखनीय है कि भारत में एक दशक से भी अधिक समय से विनिमय दर समीकरण पूँजीगत प्रवाहों से प्रभावित रहे हैं न कि चालू खाता शेषों से। स्वगत कथन के रूप में यह कह दूँ

कि भारत अधिकांशतः चालू खाता घाटे में रहा है जबकि यूएस के साथ द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष रहा है, 2018 में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कुछ अधिक। यद्यपि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) व दीर्घावधि ऋण संबंधी दीर्घावधि प्रवाह आर्थिक आधारों के मुताबिक पर्याप्त स्थिर रहे हैं, परंतु पोर्टफोलियो प्रवाहों का अपना समीकरण रहा है जो भारतीय आस्तियों (एसेट्स) पर मिलने वाले लाभ पर जितना निर्भर होते हैं, उतना ही जोखिम की भूख को प्रभावित करने वाले वैश्विक कारकों पर भी। इन परिस्थितियों में विदेशी मुद्रा बाजार में हलचल की दशा में व्यवस्था स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप के सिवा कोई बेहतर विकल्प नहीं होता। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार निर्यात अधिशेष से निर्मित नहीं हैं, बल्कि उधार के रिज़र्व हैं। प्रवाहों के अचानक पलटने पर ये जहाँ दीवार का काम करते हैं, वहीं इसके परिणाम से जूझने की क्षमता बढ़ाते हैं और वैश्विक स्थिरता में भी योगदान देते हैं।

नीतिगत व्यवस्था उन सभी निवासी आर्थिक कारकों को बचाव (हेजिंग) के साधन भी देती है जिनका एकसपोज़र विदेशी मुद्रा में है और अनिवासियों को भी जिनका रुपए में एकसपोज़र है। देश में स्थित (ऑनशोर) बाजारों में पर्याप्त गहराई और तरलता है पर इन्हें और मजबूती चाहिए। हेजिंग के कई प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं तथा इसमें और अधिक विस्तार उनके जोखिम प्रभावों की समझ के अनुसार होगा। हाल के समय में, वैश्विक संस्थान और निवेशकों ने रुपए में वर्गीकृत आस्तियों (एसेट्स) के लिए अच्छी भूख दिखाई है जो विदेशी मुद्रा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के साथ-साथ विनिमय जोखिम से भारतीय जारीकर्ताओं को बचाता भी है। इस रुझान को नीतिगत स्तर पर और समर्थन की आवश्यकता है।

संक्षेप में, मैं यह कहना चाहूँगा कि यद्यपि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संकेत हतोत्साही हैं और व्यापार तनाव व भू-राजनैतिक घटनाक्रमों से अनिश्चितताएं उभर रही हैं, मैं इस पर आशावादी हूँ कि बहुपक्षीय ढाँचे से समन्वित नीतिगत कार्रवाई और विवादों के समाधान से आगे की राह निकलेगी।

मैं इस अवसर पर दो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित करूँगा। पहला, विदेशी मुद्रा लेन-देनों का पारदर्शी व उचित कीमत-निर्धारण जिस पर विभिन्न वर्गों के उपयोगकर्ताओं ने हमारा ध्यान खींचा है। उचित मूल्य पाने की समस्या विकट थी,

विशेषतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए जिनको विभिन्न बैंकों के विदेशी मुद्रा (एफएक्स) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों के उपयोग की अनुमति नहीं थी। इस मुद्दे का हल निकालने के लिए रिज़र्व बैंक ने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म विकसित करने का निर्णय लिया जहाँ ऐसे सहभागी सीधे अपने क्रय/विक्रय आदेश रख सकेंगे। उपयोक्ताओं के लिए यह प्लेटफॉर्म अगस्त 2019 की शुरुआत से उपलब्ध है और इसमें खुदरा ग्राहकों व प्राधिकृत डीलर बैंकों से बोली/प्रस्ताव की अनुमति है जिसे अनाम (एनोनिमस) व स्वचालित (ऑटोमेटिक) रूप से मैच किया जाएगा तथा इस प्रकार उपयोगकर्ताओं को अपने व्यापार के स्तर के बारे में पूर्ण पारदर्शिता मिलेगी। बैंकों को अपने प्रोसेसिंग चार्ज अलग से घोषित व वसूल करने होंगे जिससे ग्राहक कारोबार के लिए बैंकों में स्पर्धा होगी। बैंकों से मेरा आग्रह है कि खुदरा व छोटे कारोबारी घरानों/एमएसएमई के बीच इस प्लेटफॉर्म को लोकप्रिय बनाएं।

दूसरा, फॉरेक्स बाजार के समुचित रूप से कार्य करने हेतु अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा सामान्य मार्गदर्शन के रूप में विकसित ग्लोबल फॉरेक्स कोड। इसमें सामान्य सिद्धांत (कुल 55 और 6 मुख्य सिद्धांत) हैं जिनका उद्देश्य यह है कि विभिन्न घोटालों (जैसे लिबर फिक्सिंग घोटाला आदि) के चलते बाजारों में हुई विश्वास की क्षति के बाद भरोसे को बहाल किया जाए और फॉरेक्स बाजार व इसके कार्य में अधिक विश्वास लाया जाए। कॉर्पोरेट/मध्यस्थ को यह कोड अपने आंतरिक एफएक्स ऑपरेशनों की समीक्षा / बेहतरी का तथा इन्हें वैश्विक मानकों के समकक्ष लाने का एक मौका देता है। इससे ग्राहकों, निवेशकों, प्रतिपक्षियों और व्यापक तौर पर बाजार को फॉरेक्स बाजार में लेन-देन में अच्छे तौर-तरीकों को अपनाने की कॉर्पोरेट की प्रतिबद्धता का सकारात्मक संकेत जाता है।

भारत में, सभी बैंकों ने, सिवाय एक के, और कई बैंकेतर सहभागियों ने कोड के प्रति प्रतिबद्धता वचन (एसओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं। यद्यपि कोड को स्वीकार करना स्वैच्छिक है, यहाँ उपस्थित सभी बैंकेतर सहभागियों से मेरा आग्रह है कि कोड का अध्ययन करें, अपनी प्रक्रियाओं को जाँचे-परखें और उसके बाद, वैश्विक कोड के एसओसी पर हस्ताक्षर करें।

आपके विचार-विमर्श की पूर्ण सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।